



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1878]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2017/आषाढ़ 14, 1939

No. 1878]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2017/ASADHA 14, 1939

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

का.आ. 2111(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् क्रियान्वयन एजेंसियां कहा गया है) को सहायता अनुदान उपलब्ध कराके बहिर्वर्ती अनुसंधान की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का कार्यान्वयन कर रहा है;

और मंत्रालय द्वारा स्कीम के अधीन अनुसंधान संस्थानों को दी गई सहायता अनुदान जिसमें ऐसे व्यष्टि, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार अनुसंधान परियोजनाओं के अधीन अनन्य रूप से पारितोषिक पर रखा गया है, को पारिश्रमिक के भुगतान पर उपगत व्ययों और प्रधान अन्वेषक और सह-अन्वेषकों की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते का भुगतान (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) शामिल है।

और इस स्कीम के अधीन ऐसे व्यष्टि, जिन्हें अनुसंधान सहयुक्तों, ज्येष्ठ अध्येता, कनिष्ठ अध्येता, परामर्शदाताओं और प्रमुख अन्वेषक तथा सह-अन्वेषकों को, जो अनुसंधान संस्थानों के पहले से ही कर्मचारी हैं,

सहित विशेष रूप से अनुसंधान परियोजना के प्रयोजन के लिए संविदात्मक आधार पर अन्य गैर-वैज्ञानिक स्टाफ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) के रूप में पारितोषिक पर रखा जाता है;

और उपर्युक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्वलित है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, उससे यह अपेक्षा है कि वह इस परियोजना के प्रवर्तन से 30 दिन के भीतर आधार नामांकन के लिए आवेदन करे परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंध के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट पर उपलब्ध है] का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से यह अपेक्षित है कि वह अपना क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां क्रमशः ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है वहां मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी अपेक्षित प्रबंध करें:

परंतु ऐसे व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदा दिए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पर्ची; या

(ii) निम्नलिखित पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) मतदाता पहचान पत्र; या (ii) स्थाई लेखा नंबर (पीएएन) कार्ड; या (iii) पासपोर्ट, या (iv) राशन कार्ड; या (v) कर्मचारी का सरकारी पहचान पत्र; या (vi) फोटो लगी बैंक या डाकखाने की पास बुक; या (vii) ईसीएचएस कार्ड; या ईएसआईसी कार्ड; या सीजीएचएस कार्ड; या (viii) मोटर यान अधिनियम, 1998 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया चालन अनुज्ञप्ति; या (ix) सरकारी पत्र शीर्ष पर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान पत्र जिस पर उस व्यक्ति का फोटो लगा हो; या (x) मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज; या

परंतु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेज मंत्रालय द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे:

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित उपायों सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करेगा, अर्थात्:-

(1) स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें परियोजना के अधीन अपनी नियुक्ति के 30 दिन के भीतर अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस-पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही नामांकन न करा पाए हों तो मंत्रालय अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से सुविधाजनक पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध क्रियान्वयन एजेंसियों के अभिहित अधिकारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से नामांकन कराएंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा.सं. जेड.28015/87/2014-एचपीसी (ईएमआर)-आयुष]

पी.एन. रणजीत कुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF AYUSH

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

**S.O. 2111(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of AYUSH (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is implementing the **Central Sector Scheme of Extra Mural Research** (hereinafter referred to as the Scheme) by providing Grant-in-Aid to the Public and Private Research Institutions (hereinafter referred to as the implementing agencies) as per the Scheme guidelines;

And whereas, Grant-in-Aid given by the Ministry under the Scheme to the Research Institutes *inter-alia*, covers the expenditures incurred towards payment of remuneration to the individuals who are hired exclusively under the research projects, and also payment of fee, travelling allowance and dearness allowances (hereinafter referred to as the benefits) to the Principal Investigator and the Co-Investigators, as per the Scheme guidelines;

And whereas, under the Scheme, individuals are hired as Research Associates, Senior Research Fellows, Junior Research Fellows, Consultants and other Non-Scientific Staff on contractual basis specifically for the purpose of research project along with Principal Investigator and Co-Investigators who are already employees of the Research Institutes (hereinafter together referred to as the beneficiaries);

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: -

1. (1) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment within 30 days of his or her engagement under the project, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provision of section 3 of the said Act, and such persons shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its implementing agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agencies shall make all the required arrangements to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming itself UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely: –

- (a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or  
(ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or (vii) ECHS Card; or ESIC Card; or CGHS Card; or (viii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry through its implementing agencies for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its implementing agencies shall make all the required arrangements including the following, namely: -

(1) Wide publicity and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas within 30 days of his or her engagement under the project, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its implementing agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies or the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F.No.Z.28015/87/2014-HPC (EMR)--AYUSH]

P.N. RANJIT KUMAR, Jt. Secy.